



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938

No. 63]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.आ. 72(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

रामपरा वन्यजीव अभयारण्य, लगभग 15.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और गुजरात राज्य के बांकांनेर मुख्यालय के साथ मोरठी जिले में अक्षांश 22 31'82" उत्तर और 22 34' 88 " के मध्य और 70 55'54" पूर्व और 70 58' 59" पूर्व देशांतर के मध्य अवस्थित है;

और, रामपरा वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर और सघन जैव विविधता पैच में से एक है जिसमें पौधों की कुल 270 प्रजातियां हैं, जिसमें वृक्षों की 52 प्रजातियां, झाड़ियों की 39 प्रजातियां, आरोहकों की 41 प्रजातियां, जड़ी-बूटियों की 37 प्रजातियां और घासों की 41 प्रजातियां शामिल हैं और यह चारों ओर से उत्तम सागौन वनों से घिरा हुआ है;

और, अभयारण्य में उभयचरों जैसे मेढक, टोड्स, फ्लैप-शेल कछुआ और स्टार कछुआ का आवास है और गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा और अनुसंधान (जीईईआर) संगठन के द्वारा वर्ष 1998 के अध्ययन में अभयारण्य में 10 परिवारों, 16 जेनरा और मकड़ियों की 21 प्रजातियां, सरीसृपों की 15 प्रजातियां, पक्षियों की 93 प्रजातियां और स्तनधारियों की 16 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं;

और, रामपरा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य जीव-जन्तु प्रजातियों जैसे भेड़िया, चिंकारा, लकड़बग्घा, सियार, बनविलाव, लोमड़ी, साही, बनैला सूअर, ब्लू बुल, खरगोश आदि सम्मिलित हैं, के साथ वनस्पति की कई दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियां हैं;

और, रामपरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रामपरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के लगभग 0.25 किलोमीटर और 4.25 किलोमीटर तक के मध्य चारों ओर के विस्तारित क्षेत्र को रामपरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) रामपरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 39.3351 वर्ग किलोमीटर तक होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का न्यूनतम और अधिकतम विस्तार लगभग 0.25 किलोमीटर और 4.25 किलोमीटर के मध्य होगा।

(2) रामपरा वन्यजीव अभयारण्य और रामपरा पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध 1** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) रामपरा वन्यजीव अभयारण्य के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली (जीपीएस) बिंदु और रामपरा पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध 2** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) रामपरा पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 8 ग्रामों की सूची **उपाबंध 3** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना — (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;

- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, 21, 26, 36 और सं. 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात हों संकेत, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना ;
- (iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं; और
- (v) वर्षा जल संचयन ।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय रामपरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात होंगी।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 के अंतर्गत तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343(अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित की जाएंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए ईंटों या देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006, और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014, के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	नई वृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा; (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है; (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिक संवेदी जोन या संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर, दोनों में से जो समीप हो नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं; तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
12.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	प्लास्टिक के बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।

18.	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	जैव अपघटनीय पदार्थों पुनःचक्रण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्युत लाइनों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमि में केबल डालने को बढ़ावा देना।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी परिसंपत्तियों में कांटेदार से बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
23.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
27.	वन उत्पाद और गैर लकड़ी उत्पाद एकत्रित करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	ट्रेकिंग और शिविर लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	एक से दस गेडियंट तक के ढालू पहाड़ी पर और किसी नदी, नहर और उप नदी के तट से 100 मीटर तक भी कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति द्वारा अन्यथा अनुज्ञात नहीं कर दिया गया हो।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंध।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	चालू कृषि पद्धति, पौधा रोपण और अन्य वानिकी क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पौधा रोपण और अन्य वानिकी क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरण संबंधी जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (क) कलेक्टर, मोरबी -अध्यक्ष;
- (ख) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला एक प्रतिनिधि -सदस्य;
- (ग) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;
- (घ) क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोरबी -सदस्य;
- (ङ.) संबंधित क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार -सदस्य;
- (च) गुजरात सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;
- (छ) पारिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में गुजरात सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(ज) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
(झ) उप वन संरक्षक (अभयारण्य का प्रभारी), राजकोट	-सदस्य- सचिव।

निर्देश निबंधन

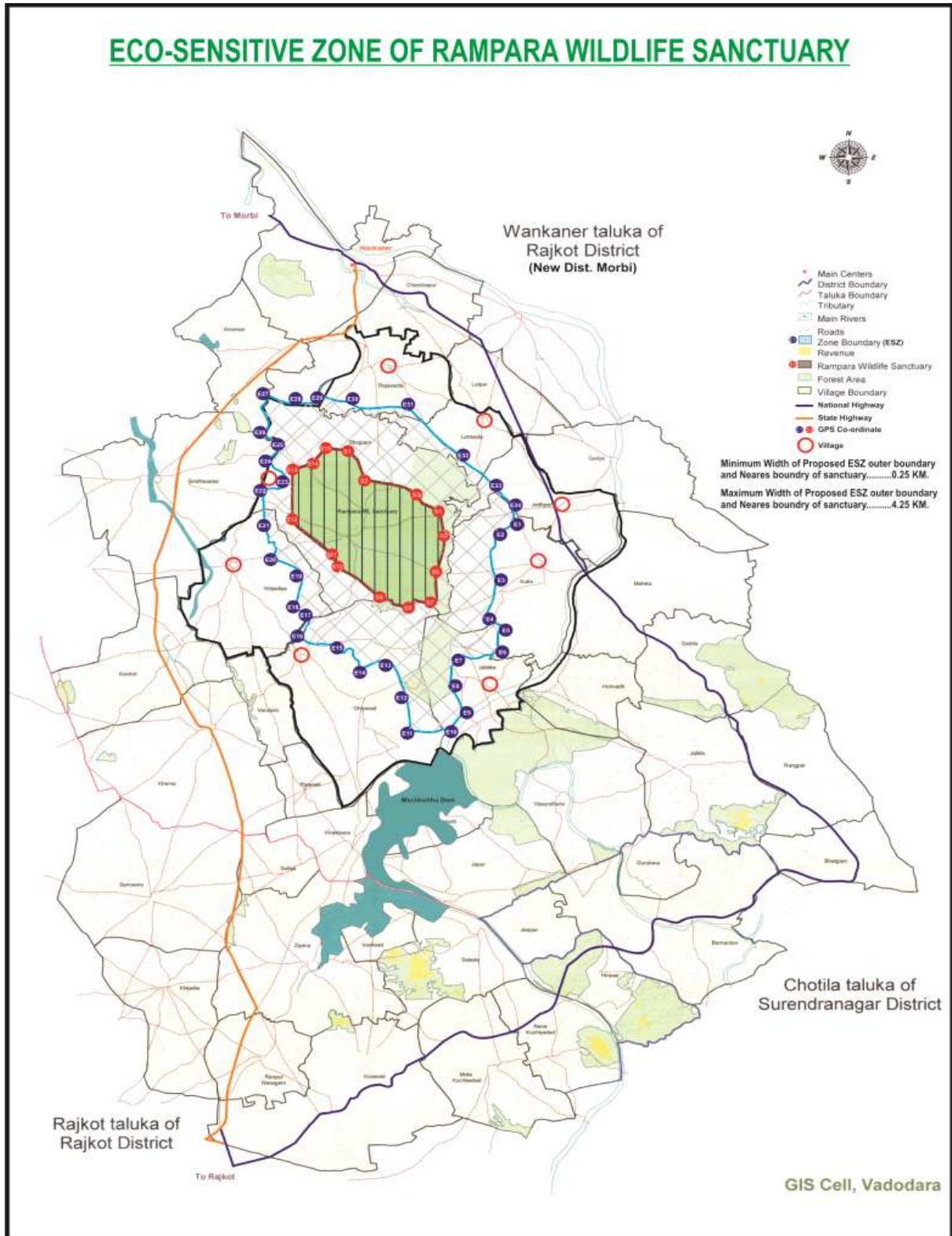
- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति अंतिम अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
 - (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
 - (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
 - (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
 - (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
 - (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
 - (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध 4** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
 - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
 - (9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 6.** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/31/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध 1

रामपरा वन्यजीव अभयारण्य और रामपरा के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानिचत्र



उपाबंध 2

संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिक संवेदी जोन के सीमा बिंदुओं और निर्देशांकों का वर्णन

क. रामपरा वन्यजीव अभयारण्य

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	2	3
एस1	उ 22°33'18.9"	पू 70°56'37.8"
एस 2	उ 22°32'48.2"	पू 70°56'54.1"
एस 3	उ 22°32'30.9"	पू 70°57'46.9"
एस 4	उ 22°32'13.6"	पू 70°58'08.4"
एस 5	उ 22°31'45.0"	पू 70°58'14.5"
एस 6	उ 22°31'08.0"	पू 70°58'05.4"
एस 7	उ 22°30'38.5"	पू 70°58'07.1"
एस 8	उ 22°30'30.2"	पू 70°57'39.6"
एस 9	उ 22°30'39.6"	पू 70°57'11.6"
एस 10	उ 22°31'13.1"	पू 70°56'28.2"
एस 11	उ 22°31'27.0"	पू 70°56'23.2"
एस 12	उ 22°32'04.3"	पू 70°55'43.0"
एस 13	उ 22°32'58.0"	पू 70°55'43.5"
एस 14	उ 22°33'07.1"	पू 70°56'03.8"
एस 15	उ 22°33'21.4"	पू 70°56'16.0"

ख. पारिस्थितिक संवेदी जोन का रामपरा वन्यजीव अभयारण्य

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
ई1	उ 22°31'50.1"	पू 70°59'28.1"	ई 18	उ 22°30'31.0"	पू 70°55'36.2"
ई 2	उ 22°31'39.7"	पू 70°59'02.0"	ई 19	उ 22°31'14.4"	पू 70°55'35.3"
ई 3	उ 22°31'01.9"	पू 70°59'08.9"	ई 20	उ 22°31'19.0"	पू 70°55'21.5"
ई 4	उ 22°30'21.5"	पू 70°58'59.8"	ई 21	उ 22°32'10.0"	पू 70°54'53.8"
ई 5	उ 22°30'10.1"	पू 70°59'09.1"	ई 22	उ 22°32'44.1"	पू 70°55'07.4"
ई 6	उ 22°29'39.8"	पू 70°59'05.8"	ई 23	उ 22°32'48.6"	पू 70°55'31.5"
ई 7	उ 22°29'34.0"	पू 70°58'20.1"	ई 24	उ 22°33'02.0"	पू 70°55'14.7"

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
ई 8	उ 22°28'56.3"	पू 70°58'12.7"	ई 25	उ 22°33'30.2"	पू 70°55'29.0"
ई 9	उ 22°28'27.0"	पू 70°58'23.2"	ई 26	उ 22°33'39.4"	पू 70°55'07.4"
ई 10	उ 22°28'18.2"	पू 70°58'15.3"	ई 27	उ 22°34'27.0"	पू 70°55'05.1"
ई 11	उ 22°28'33.3"	पू 70°57'29.3"	ई 28	उ 22°34'18.8"	पू 70°55'33.2"
ई 12	उ 22°29'14.5"	पू 70°57'26.1"	ई 29	उ 22°34'22.0"	पू 70°56'01.6"
ई 13	उ 22°29'29.8"	पू 70°57'17.6"	ई 30	उ 22°34'09.1"	पू 70°56'22.9"
ई 14	उ 22°29'28.7"	पू 70°56'36.7"	ई 31	उ 22°33'53.2"	पू 70°57'21.8"
ई 15	उ 22°29'51.7"	पू 70°56'26.7"	ई 32	उ 22°33'28.6"	पू 70°58'12.1"
ई 16	उ 22°30'01.6"	पू 70°55'42.9"	ई 33	उ 22°32'42.5"	पू 70°59'05.7"
ई 17	उ 22°30'29.2"	पू 70°55'45.4"	ई 34	उ 22°32'25.2"	पू 70°59'22.7"

उपाबंध 3

रामपरा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क. ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	तालुका के नाम	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर)			टिप्पणियाँ
			वन क्षेत्र	गैर-वन क्षेत्र	कुल क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7
1	खिजादिया	बांकानेर	-	320.30	320.30	मोरबी जिला
2	धियावाड	बांकानेर	262.51	553.79	816.30	„
3	खोठी	बांकानेर	10.80	608.20	619.00	„
4	लिम्बाला	बांकानेर	-	143.90	143.90	„
5	जोधपार	बांकानेर	-	72.30	72.30	„
6	विदी भोजपारा	बांकानेर	251.34	1303.99	1555.33	„
7	राजा वदला	बांकानेर	-	19.50	19.50	„
8	जलसिका	बांकानेर	190.00	196.88	386.88	„
	कुल क्षेत्र		714.65	3218.86	3933.51	

ख. रामपरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित ग्रामों की सर्वे संख्या का वर्णन

क्र. सं.	ग्राम के नाम	तालुका	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित राजस्व और वन सर्वे सं.	गैर वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वन क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सीमाएं	
1	विदी भोजपारा	बांका नेर	1 से 15, 28 से 66, 67/1, 67/5, 69, 70, 71/ पी और 72 की सर्वे सं.।	1303.99	251.34	1555.33	उत्तर	बांका नेर (चन्द्रापुर), राजा बदला और लिम्बाला की ग्राम सीमाएं।
							पूर्व	जोधपार और खोटी की ग्राम सीमाएं।
							दक्षिण	धियावाड की ग्राम सीमाएं।
							पश्चिम	खिजादिया, सिंघावदर और अमरसार की ग्राम सीमाएं और सर्वे सं. 27/1, 27/3, 24, 67/4, 15/1, 2, 3, और 71/पी।
2	राजा बदला	बांका नेर	236 से 240, 242, 243/1, 243/3, 244/ पी, 273, 280, 281/1 पी, और 349/ पी की सर्वे सं.।	19.50	-	19.50	उत्तर	सर्वे सं. 235, 232/1, 241/1, 241/6, 243/2, 244, 245/2, 272/1, 274/2, 277/1, 280/1, 281/1, और 349/पी.
							पूर्व	सर्वे सं. 274/1, 280/1, 281/1।
							दक्षिण	रामपरा(विदी भोजपारा) की ग्राम सीमाएं।
							पश्चिम	रामपरा(विदी भोजपारा) की ग्राम सीमाएं।
3	लिम्बाला	बांका नेर	34 से 43, 104 से 138, और 185/ पी की सर्वे सं.।	143.90	-	143.90	उत्तर	राजा बदला की ग्राम सीमाएं।
							पूर्व	सर्वे सं. 185/पी, 148/1, 148/2, 147/1, 139/1, 99, 100, 101/1, 2, 3, 72/1, 2, 103, 44/2, 45/1, 2, 46/1, 2, 47 और 33।
							दक्षिण	रामपरा (विदी भोजपारा) और जोधपार की ग्राम सीमाएं।
							पश्चिम	रामपरा(विदी भोजपारा) की ग्राम सीमाएं।
4	जोधपार	बांका नेर	73 से 79 और 355/1 पी की सर्वे सं.।	72.30	-	72.30	उत्तर	रामपरा(विदी भोजपारा) और लिम्बाला की ग्राम सीमाएं।
							पूर्व	सर्वे सं. 355/1 पी, 68, और 72/2।
							दक्षिण	खोटी की ग्राम सीमाएं।
							पश्चिम	रामपरा (विदी भोजपारा) की ग्राम सीमाएं।
5	खोटी	बांका नेर	9 से 19, 23 से 28, 45 से 95, 359 से 379, 380/1 पी, 380/16, 380/12 और 380/11 की सर्वे सं.।	608.20	10.80	619.00	उत्तर	जोधपार की ग्राम सीमाएं।
							पूर्व	जोधपार की ग्राम सीमाएं और सर्वे सं. 96, 99/1, 100, 101, 43/2, 43/1, 44/1, 44/2, 30/2, 30/1, 29, 22/1, 20, 21, 8, 388, 389, 347, 325, 380/13 और 380/1 पी।
							दक्षिण	जलसिका की ग्राम सीमाएं।
							पश्चिम	रामपरा (विदी भोजपारा) की ग्राम सीमाएं।
6	जलसिका	बांका नेर	106/ पी, 104, 97, 95, 96 और 103 की सर्वे सं.	196.88	190.00	386.88	उत्तर	रामपरा (विदी भोजपारा) और खोटी की ग्राम सीमाएं।
							पूर्व	सोभला (खोटी) और सर्वे सं. 106/पी, 94, 98, 99, 102 और 105 की ग्राम सीमाएं।
							दक्षिण	मच्छु नदी।
							पश्चिम	धियावाड की ग्राम सीमाएं।
7	धियावाड	बांका नेर	178/ पी, 179/ पी, 148/1 पी, 180 से 200, 250 से 308, 311 से 325, 326/13 और 326/1 पी की सर्वे सं.।	553.79	262.51	816.30	उत्तर	रामपरा (विदी भोजपारा) और खिजादिया की ग्राम सीमाएं।
							पूर्व	जलसिका की ग्राम सीमाएं।
							दक्षिण	सर्वे सं. 178/पी और 177।
							पश्चिम	खिजादिया की ग्राम सीमाएं और सर्वे सं. 169, 179/पी, 148/पी, 206/3, 204, 203/2, 203/1, 206/1, 207/4, 207/3, 207/5, 208, 209, 213 से 216, 242 से

क्र. सं.	ग्राम के नाम	तालुका	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित राजस्व और वन सर्वे सं.	गैर वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वन क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सीमाएं	
								246, 248, 249, 310, 329/2, 326/4, 326/6, और 5 ।
8	खिजादिया	बांका नेर	321/1पी, 284 से 302, 304 से 314, 322 से 326, 358/1, 359 से 368, 371 और 387 से 403 की सर्वे सं. ।	320.30	-	320.30	उत्तर	रामपरा (विदी भोजपारा) की ग्राम सीमाएं ।
							पूर्व	रामपरा (विदी भोजपारा) की ग्राम सीमाएं ।
							दक्षिण	धियावाड की ग्राम सीमाएं ।
							पश्चिम	सर्वे सं.321/3, 276, 277, 278/3, 279, 280, 283, 271/3, 271/1, 270, 321/1पी, 303, 316, 320, 319, 318, 327, 328, 357, 358/2, 370/2, 370/1, 372/3, 386, 404/2, 404/1, 406, 407 और 410 ।
			कुल:	3218.86	714.65	3933.51		

उपाबंध 4

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 9th January, 2017

S.O. 72(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so

specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Rampara Wildlife Sanctuary is spread over an area of 15.01 square kilometre and situated between latitude 22 31' 82" N and 22 34' 88" N and between 70 55' 54" E and 70 58' 59" E longitude in Morbi district with the headquarters at Wankaner in the State of Gujarat.

And whereas, the Rampara Wildlife Sanctuary is one of the richest and compact bio-diversity patches with a total 270 species of plants which include 52 species of trees, 39 species of shrubs, 41 species of climbers, 97 species of herbs and 41 grasses and it is covered on all sides by very good quality teak forest;

And whereas, the sanctuary is a home to Amphibians such as Frogs, Toads, Flap-shell Turtle and Star tortoise and the study carried out by the Gujarat Ecological Education and Research (GEER) foundation in the year 1998 has recorded 10 families, 16 genera and 21 species of spiders in the sanctuary, 15 species of reptiles, 93 species of birds and 16 species of mammals;

And whereas, the Rampara Wildlife Sanctuary includes Wolf, Chinkara, Hyana, Jackal, Jungle Cat, Fox, Porcupine, Wild boar, Blue bull, Hare, etc. as the major faunal species along with many rare and endangered species of flora;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Rampara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying between 0.25 km and 4.25 kilometer around the boundary of Rampara Wildlife Sanctuary of the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1). The area of Eco-sensitive Zone of Rampara Wildlife Sanctuary is 39.3351 square kilometre and the minimum and maximum extent of the Eco-sensitive Zone is 0.25 kilometer and 4.25 kilometer surrounding the protected area.

(2). Map of Rampara Wildlife Sanctuary and Rampara Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3). The Global Positioning System (GPS) points of Rampara Wildlife Sanctuary and Rampara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-II**.

(4). The list of the eight villages falling within Rampara Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism ;
- (v) Municipal ;
- (vi) Revenue ;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Gujarat State Pollution Control Board;
- (ix) Irrigation; and
- (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 21, 26, 36 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities; and
- (v) rainwater harvesting;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan;

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government;

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Rampara Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of the final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of the final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or Gujarat State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.**—(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE		
S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for <i>bone fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
15.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Erection of electric cables	Regulated under applicable laws.
19.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
20.	Installation of electric lines.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their

		properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
25.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Collection of non-timber forest products	Regulated under applicable laws.
28.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
29.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
30.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
32.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
39.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Skill development.	Shall be actively promoted.
41.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (a) Collector, Morbi—Chairman;

- (b) A representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India—Member;
- (c) one representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of India—Member;
- (d) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Morbi—Member;
- (e) Senior Town Planner of the area —Member;
- (f) a representative of the Department of Forests and Environment, Government of Gujarat—Member;
- (g) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Ministry of Environment and Forest, Government of India—Member;
- (h) Member State Biodiversity Board—Member;
- (i) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Rajkot—Member Secretary.

Terms of reference.— (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of the final notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of the final notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per performa appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

(9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

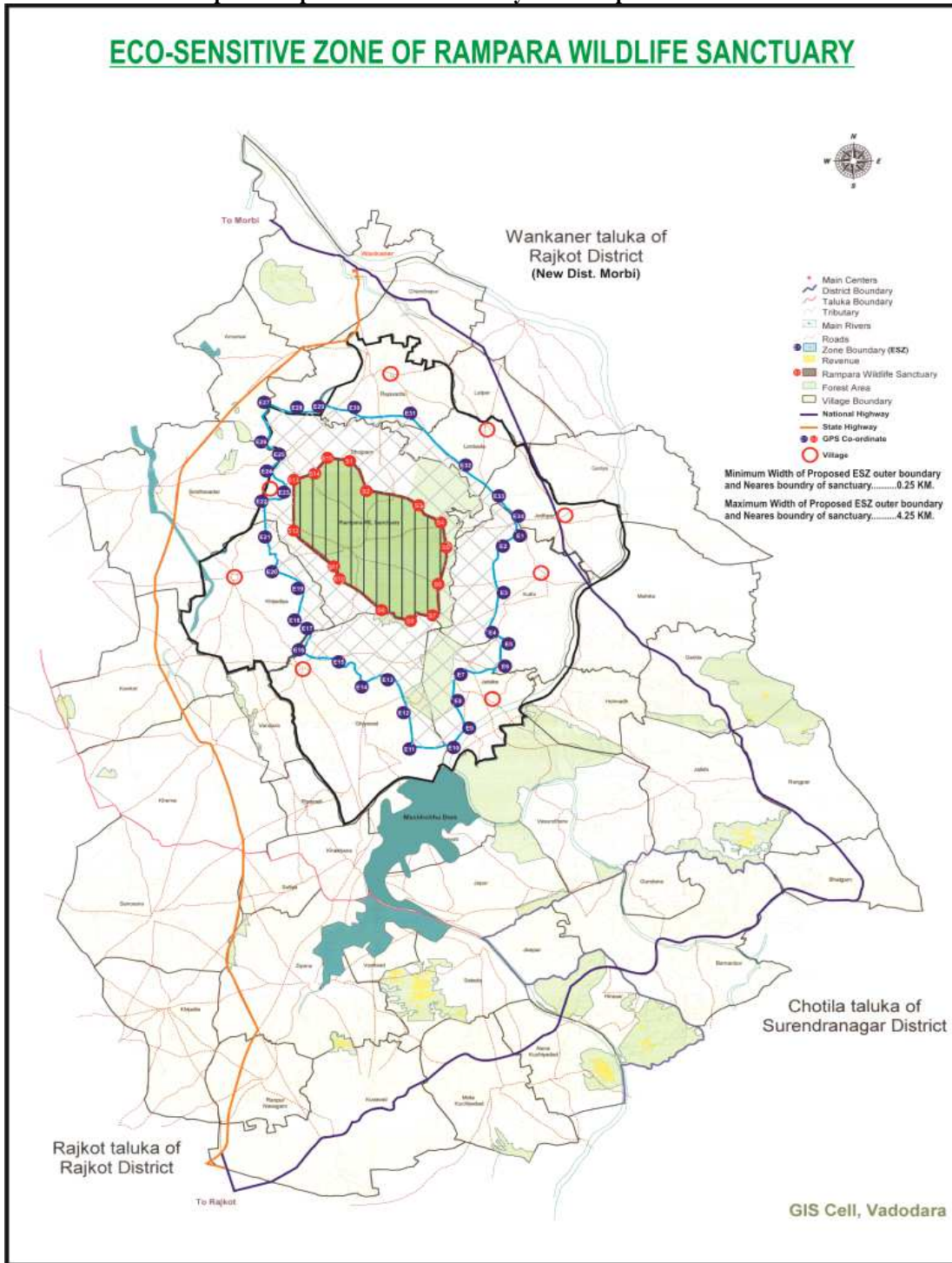
6. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/31/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Rampara Wildlife Sanctuary and Rampara Eco-sensitive Zone



Annexure-II

Boundary Points and Co-ordinates details of Protected Area and the Eco-Sentive Zone**A. Rampara Wildlife Sanctuary**

SR.NO.	LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3
S1	N 22°33'18.9"	E 70°56'37.8"
S2	N 22°32'48.2"	E 70°56'54.1"
S3	N 22°32'30.9"	E 70°57'46.9"
S4	N 22°32'13.6"	E 70°58'08.4"
S5	N 22°31'45.0"	E 70°58'14.5"
S6	N 22°31'08.0"	E70°58'05.4"
S7	N 22°30'38.5"	E 70°58'07.1"
S8	N 22°30'30.2"	E 70°57'39.6"
S9	N 22°30'39.6"	E 70°57'11.6"
S10	N 22°31'13.1"	E 70°56'28.2"
S11	N 22°31'27.0"	E 70°56'23.2"
S12	N 22°32'04.3"	E 70°55'43.0"
S13	N 22°32'58.0"	E 70°55'43.5"
S14	N 22°33'07.1"	E 70°56'03.8"
S15	N 22°33'21.4"	E 70°56'16.0"

B. Eco-sensitive Zone of Rampara Wildlife Sanctuary

SR. No.	LATITUDE	LONGITUDE	SR. No.	LATITUDE	LONGITUDE
E1	N 22°31'50.1"	E 70°59'28.1"	E18	N 22°30'31.0"	E 70°55'36.2"
E2	N 22°31'39.7"	E 70°59'02.0"	E19	N 22°31'14.4"	E 70°55'35.3"
E3	N 22°31'01.9"	E 70°59'08.9"	E20	N 22°31'19.0"	E 70°55'21.5"
E4	N 22°30'21.5"	E 70°58'59.8"	E21	N 22°32'10.0"	E 70°54'53.8"
E5	N 22°30'10.1"	E 70°59'09.1"	E22	N 22°32'44.1"	E 70°55'07.4"
E6	N 22°29'39.8"	E 70°59'05.8"	E23	N 22°32'48.6"	E 70°55'31.5"
E7	N 22°29'34.0"	E 70°58'20.1"	E24	N 22°33'02.0"	E 70°55'14.7"
E8	N 22°28'56.3"	E 70°58'12.7"	E25	N 22°33'30.2"	E 70°55'29.0"
E9	N 22°28'27.0"	E 70°58'23.2"	E26	N 22°33'39.4"	E 70°55'07.4"
E10	N 22°28'18.2"	E 70°58'15.3"	E27	N 22°34'27.0"	E 70°55'05.1"
E11	N 22°28'33.3"	E 70°57'29.3"	E28	N 22°34'18.8"	E 70°55'33.2"
E12	N 22°29'14.5"	E 70°57'26.1"	E29	N 22°34'22.0"	E 70°56'01.6"
E13	N 22°29'29.8"	E 70°57'17.6"	E30	N 22°34'09.1"	E 70°56'22.9"
E14	N 22°29'28.7"	E 70°56'36.7"	E31	N 22°33'53.2"	E 70°57'21.8"
E15	N 22°29'51.7"	E 70°56'26.7"	E32	N 22°33'28.6"	E 70°58'12.1"
E16	N 22°30'01.6"	E 70°55'42.9"	E33	N 22°32'42.5"	E 70°59'05.7"
E17	N 22°30'29.2"	E 70°55'45.4"	E34	N 22°32'25.2"	E 70°59'22.7"

Annexure-III

Details of Villages falling within the areas of Rampara Wildlife Sanctuary.

A. List of villages

S.No	Name of Village	Name of Taluka	Proposed Area (Hectare)			Remarks
			Forest Area	Non-Forest Area	Total Area	
1	2	3	4	5	6	7
1	Khijadia	Wankaner	-	320.30	320.30	Morbi district
2	Ghiyavad	Wankaner	262.51	553.79	816.30	„
3	Khothi	Wankaner	10.80	608.20	619.00	„
4	Limbala	Wankaner	-	143.90	143.90	„
5	Jodhapar	Wankaner	-	72.30	72.30	„
6	Vidi Bhojapara	Wankaner	251.34	1303.99	1555.33	„
7	Raja Vadala	Wankaner	-	19.50	19.50	„
8	Jalsika	Wankaner	190.00	196.88	386.88	„
Total Area			714.65	3218.86	3933.51	

B. DETAILS OF VILLAGES SURVEY NUMBERS TO BE INCLUDED IN RAMPARA WILDLIFE SANCTUARY.

S. No.	Name of Village	Taluka	Revenue and Forest Survey Nos included in Eco-fragile Zone	Non-Forest Area in (Hectare)	Forest Area in Hectare	Total Area in Hectare	Boundaries	
1	Vidi Bhojapara	Wankaner	Survey Nos of 1 to 15, 28 to 66, 67/1, 67/5, 69,70,71/p and 72.	1303.99	251.34	1555.33	North	Village Boundaries of Wankaner (Chandrapur), Rajavadala and Limbada.
							East	Village Boundaries of Jodhpur and Kothi
							South	Village Boundaries of Ghiyavad.
							West	Village Boundaries of Khijadiya, Sindhavadar and Amarsar and Survey No. 27/1, 27/3, 24, 67/4, 15/1, 2, 3, and 71/p.
2	Rajavadala	Wankaner	Survey Nos of 236 to 240, 242, 243/1, 243/3, 244/p, 273, 280, 281/1p, and 349/p.	19.50	-	19.50	North	Survey No. 235, 232/1, 241/1, 241/6, 243/2, 244, 245/2, 272/1, 274/2, 277/1, 280/1, 281/1, and 349/p.
							East	Survey No. 274/1, 280/1, 281/1.
							South	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara).
							West	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara).
3	Limbada	Wankaner	Survey Nos of 34 to 43, 104 to 138, and 185/p.	143.90	-	143.90	North	Village Boundaries of Rajavadala.
							East	Survey No. 185/p, 148/1, 148/2, 147/1, 139/1, 99, 100, 101/1, 2, 3, 72/1,2.

S. No.	Name of Village	Taluka	Revenue and Forest Survey Nos included in Eco-fragile Zone	Non-Forest Area in (Hectare)	Forest Area in Hectare	Total Area in Hectare	Boundaries	
								103, 44/2, 45/1, 2, 46/1, 2, 47 and 33.
							South	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara) and Jodhpur.
							West	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara).
4	Jodhpar	Wankaner	Survey Nos of 73 to 79 and 355/1p .	72.30	-	72.30	North	Village Boundaries of Rampara (Vidi . bhojapara) and Limbada.
							East	Survey No. 355/1p, 68, and 72/2.
							South	Village Boundaries of Kothi.
							West	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara).
5	Kothi	Wankaner	Survey Nos of 9 to 19, 23 to 28, 45 to 95, 359 to 379, 380/1p, 380/16, 380/12 and 380/11.	608.20	10.80	619.00	North	Village Boundaries of Jodhpur.
							East	Village Boundaries of Jodhpur & survey No. 96, 99/1, 100, 101, 43/2, 43/1, 44/1, 44/2, 30/2, 30/1, 29, 22/1, 20, 21, 8, 388, 389, 347, 325, 380/13 and 380/1p.
							South	Village Boundaries of Jalsika.
							West	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara).
6	Jalsika	Wankaner	Survey Nos of 106/p, 104, 97, 95, 96 and 103.	196.88	190.00	386.88	North	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara) and Kothi.
							East	Village Boundaries of Sobhala (Kothi) and Survey No. 106/p, 94, 98, 99, 102 and 105.
							South	Macchu river.
							West	Village Boundaries of Ghiyavad.
7	Ghiyavad	Wankaner	Survey Nos of 178/p, 179/p, 148/1p, 180 to 200, 250 to 308, 311 to 325, 326/13 and 326/1p.	553.79	262.51	816.30	North	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara) and Khijadiya.
							East	Village Boundaries of Jalsika.
							South	Survey No. 178/p and 177.
							West	Village Boundaries of Khijadiya & Survey No. 169, 179/p, 148/p, 206/3, 204, 203/2, 203/1, 206/1, 207/4, 207/3, 207/5, 208, 209, 213 to 216, 242 to 246, 248, 249, 310, 329/2, 326/4, 326/6, & 5.

S. No.	Name of Village	Taluka	Revenue and Forest Survey Nos included in Eco-fragile Zone	Non-Forest Area in (Hectare)	Forest Area in Hectare	Total Area in Hectare	Boundaries	
8	Khijadiya	Wankaner	Survey Nos of 321/1p , 284 to 302, 304 to 314, 322 to 326, 358/1, 359 to 368, 371 and 387 to 403.	320.30	-	320.30	North	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara).
							East	Village Boundaries of Rampara (Vidi . Bhojapara).
							South	Village Boundaries of Ghiyavad.
							West	Survey No. 321/3, 276, 277, 278/3, 279, 280, 283, 271/3, 271/1, 270, 321/1p, 303, 316, 320, 319, 318, 327, 328, 357, 358/2, 370/2, 370/1, 372/3, 386, 404/2, 404/1, 406, 407 and 410.
			TOTAL:	3218.86	714.65	3933.51		

ANNEXURE-IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); [Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.